

टाल मटोल करते हुए दिनांक 19.08.2007 को जरिये परिवार साफ इन्कार कर दिया। इसी कारण दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया। उक्त आराजी अदालत वाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 02 लेण्ड होल्डर हाने से जरूरी पक्षकार है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे:- (क) चक 4 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 58 के 24.5 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 22 के 1 बीघा, इस प्रकार कुल 25.05 बीघा जो कि वर्तमान खाता संख्या 81/76 मुरब्बा नम्बर 5, 71 एवं 80 के रूप में दर्ज है, का वादी को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार कारतकार हकदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रकबा की हद तक उसके नाम से खातेदारी दर्ज किया जावे। (ख) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि वादी को उक्त आराजी 25.05 बीघा से जबरन खिलाफ कानून वेदखल करने से बाज व ममनू रहे। (ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे। (घ) अन्य अनुतोष जो हित में हो देवे।

प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

प्रतिवादी संख्या 02 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा उपरिथत आकर जवाब वादपत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त शीर्षक के मूल वाद अनुसूचित जाति से सम्बन्धित खातेदार की कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा के आधार पर अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से वादी को प्रश्नगत कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं होते हैं। इसलिये विचाराधीन वादपत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार वाद पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता एवं पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों एवं जवाब राज्यपक्ष का अवलोकन करते हुये प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। एवं माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2015 आर.आर.डी 556 का ससम्मान अध्ययन किया गया।

प्रश्नगत कृषि भूमि चक 4 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/76 मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 58 के 24.05 बीघा बरानी कृषि भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 22 में 1.00 बीघा कुल 25.05 बीघा कृषि भूमि पंजीबद्ध दस्तावेज बैयनामा दिनांक 02 फरवरी, 1971 के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को बिक्रीत किया गया है। उक्त शीर्षक वाद अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने को कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा मत माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा 2015 आर.आर.डी. 556 में प्रतिपादित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से आवेदक का प्रश्नगत कृषि भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार सृजित नहीं होते हैं। अतः विचाराधीन वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

॥ आदेश ॥

वादी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा एवं राज पैरोकार की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है। वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(स्वाति गुप्ता)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
कार्यालय न्यायिक दण्डनायक
श्रीगंगानगर
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर